भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 336
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 (15 अग्रहायण, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

कृषक उत्पादक संगठनों का गठन

336 **श्री संजय राउत:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभ के लिए देश के विभिन्न भागों में 1100 नए अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना करके प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सुदृढ करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार एफपीओ योजना में पैक्स के एकीकरण पर जोर दे रही है ताकि किसान उत्पादन आदानों और कृषि उपकरणों की आपूर्ति जैसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार कर सकें; और
(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित एफपीओ का ब्यौरा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ मान्यवर।

(ख) से (घ): भारत सरकार देश भर में 10,000 नए एफपीओ का गठन कर उनको प्रोत्साहन देने के लिए "10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित कर रही है । इससे किसानों को अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, *एकोनॉमीस ऑफ स्केल* का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत कम करने और कृषि उपज के एकत्रीकरण के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा,जिससे सतत आय की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जाएगी।

यह योजना फरवरी 2019-20 में 5 साल की अवधि यानी 2023-24 तक के लिए शुरू की गई थी जिसकी प्रतिबद्धता अवधि 2027-28 तक है। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहित 14 कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरक्त, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) को सुदृढ करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना "10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन" के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को अतिरिक्त 1,100 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

एफपीओ के साथ पैक्स का एकीकरण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघों के माध्यम से उन्हें आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य के माध्यम से मौजूदा पैक्स को सुदृढ करेगा। इससे पैक्स की आर्थिक गतिविधियों में विविधता आएगी, जिससे वे आय के नए और स्थिर स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम होंगे।

इसके अतिरक्त, केंद्रीय क्षेत्रक योजना "10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन" के अंतर्गत, देश भर में कुल 7476 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 516 महाराष्ट्र राज्य में हैं।

*****